

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2007

खण्ड-1, अंक-6

अधिकृत विवरण



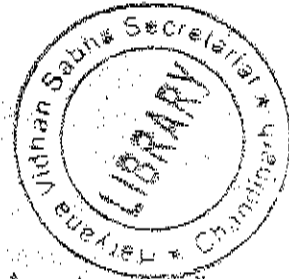
विषय सूची

शुक्रवार, 16 मार्च, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 17
अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 23
शोक प्रस्ताव	(6) 23
वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(6) 24

मूल्य :

₹ 48



हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 16 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब सवाल-जवाब होंगे।

Metalling of Bithal-Lath and Bithal-Jauli Road

*582. Shri Dharampal Singh Malik : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to metalling the Bithal-Lath and Bithal-Jauli road of District Sonapat; and
- If so, the time by which the above said roads are likely to be metalled?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) :

- No. Sir.
- The question does not arise.

श्री० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि यह बहुत पुरानी रोड़ है और आज तक इसकी रिपेयर नहीं हुई। मंत्री जी कृपया यह बतायें कि इस सड़क को पोल्तब्यूंडी (पी०एण्ड०आर०) बनायेगा या मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जायेगी ताकि हम संबंधित विभाग से जल्द रिक्वेस्ट कर सकें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इनमें एक रोड़ पांच करम की है और दूसरी चार से पांच करम की है। वे दोनों सड़कें मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जायेंगी और इन सड़कों को जल्दी ही बनवा दिया जायेगा और इन पर 70 लाख 29 हजार रुपये की लागत आयेगी। अगर मलिक साहब पहले ही कह देते तो हम इन सड़कों को पहले बनवा देते।

श्री० धर्मपाल सिंह मलिक : धन्यवाद सर।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान जो सड़कें रिपेयर की जा रही हैं उसकी डिस्ट्रिक्टवाइज लिस्ट मेरे पास है उसमें केवल पांच सड़कों को रिपेयर करने का ब्यौरा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हिसार जिले में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कितनी सड़कें आगे आने वाले वित्तीय वर्ष 2007-2008 में रिपेयर करवाने की योजना सरकार ने बनाई है ?

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह इस सवाल से संबंधित नहीं है इसलिए वे अलग से लिखित रूप में सवाल पूछ लें तो उनको विस्तार से शीशे की तरह साफ जवाब मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां जी, डाक्टर इन्दौरा साहब आपने कोई सप्लीमेंट्री पूछनी है।

डा० सुशील इन्दौरा : नहीं सर।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लागा चाहूंगा कि अटोली से बहरोड़ रोड़ कांटी खेड़ी गांव तक टूटा हुआ है। पिछले एक-डेढ़ साल से इस रोड़ को बनवाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। यह रोड़ पी०डब्ल्यू०डी०(बी०एंड आर०) विभाग से संबंधित है, मार्केटिंग बोर्ड से संबंधित नहीं है और इसकी लम्बाई करीबन 10-12 कि०मी० की है। कांटी खेड़ी गांव से आगे की सड़क बहरोड़ तक राजस्थान सरकार ने बनवा दी है। यह बोर्ड हरिया की सड़क है, इसको मंत्री जी जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें।

Mr. Speaker : Yadav Ji, it is very difficult to reply, आप इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछ लेना और लिखित में भेज देना, मंत्री जी आपको जवाब दे देंगे।

New Plants/Projects for Generating Electricity

*602. Dr. Sushil Indora : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any new plants/projects for generating the electricity or signed any M.O.U. during the financial year 2005-06 and 2006-07; and
- if so, the number of plants/projects on which the construction work has been started, togetherwith the time limit by which the above said projects will start generating the power ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

- Yes Sir.
- The construction work of 1200 MW Hisar Thermal project has started. The two units are scheduled to be commissioned in December, 2009 and March, 2010. Another power project of 600 MW (2x300 MW) capacity is under construction in Yamuna Nagar. The Units-I & II of this project are scheduled to be commissioned by Nov., 2007 and Feb., 2008. An MOU has been signed on 24-8-06 between NTPC, HPGCL (on behalf of Govt. of Haryana) & Indraprastha Power Generation Corporation Limited (on behalf of Govt. of NCT, Delhi) for establishing a 1500 MW plant in Distt. Jhajjar in Haryana as a joint venture from which Haryana will get 750 MW. The work of this project is likely to be awarded in April, 2007. Further, the process of selecting an Independent Power Producer (IPP), on the basis of tariff based competitive bids for setting up of a 1000 plus MW coal based project in Distt. Jhajjar has been initiated, in the year 2006-07.

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत है और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी मान चुके हैं। सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह नये-नये प्रोजेक्ट लगाकर या ज्वाइंट वेंचर के एम०ओ०यू० साईन करके प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वर्ष 2005-06 में कोई एम०ओ०यू० सरकार की तरफ से साईन किया गया था और जैसा कि मैंने सवाल पूछा है। इसका जवाब 'नहीं' में आया है। अगर कोई एम०ओ०यू० वर्ष 2005-06 में साईन नहीं किया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय झज्जर में अगस्त, 2005 में जो गैस बेस्ड पावर प्लांट का नींव पत्थर रखकर आये थे उसका नींव पत्थर किस आधार पर रखा गया था। क्या बिना एम०ओ०यू० साईन हुए ही नींव पत्थर रख दिया गया था ? दूसरा मंत्री जी ने बताया है कि 1200 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल प्लांट हिसार में लगाया जा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा जी, आपके पहले सवाल का जवाब तो आपको मैं ही बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अगस्त, 2005 में झज्जर में किसी भी पावर प्लांट का नींव पत्थर नहीं रखा। आप जिस तरह से सदन में गलत इन्फार्मेशन देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई परोपर जानकारी हो उसी का जिक्र आप सदन में किया करो।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यह फरीदाबाद की बात थी और मेरे दिनाग में झज्जर आ गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो 1200 मेगावाट का थर्मल प्लांट हिसार में लगाया जा रहा है क्या उस प्लांट के लिए गैस लिकेज का प्रावधान हो गया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वह प्लांट कोल बेस्ड है, गैस बेस्ड नहीं है, फिर गैस लिकेज की बात कहां से आ गई।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कोल लिकेज की बात पूछना चाह रहा था कि उस प्लांट के लिए कोल लिकेज का प्रावधान हो गया या नहीं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी ने झज्जर में मुख्यमंत्री जी द्वारा नींव पत्थर रखने की बात की थी। उसका जवाब तो आपने ही दे दिया है। इंदौरा जी, बिजली की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके साथी बिजली के बिल तो भरते नहीं हैं और बिजली की तारों पर कुण्डी लगाकर बिजली चोरी करते हैं, लेकिन अब हम ऐसी बढ़िया तारें लगावायेंगे यदि कोई उन पर कुण्डी लगायेगा तो वैसे ही उड़ जायेगा। (विघ्न)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी लीक से हटकर बात कर रहे हैं। मंत्री जी को चाहिए कि वे परोपर तैयारी करके आर्थे और सदन में सही जवाब दें। मंत्री जी को इस तरह से इधर-उधर की बात नहीं करनी चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि प्रदेश में कितने बिजली के प्लांट लगाये जा रहे हैं। इसका जवाब वैसे तो पहले ही दे दिया गया है फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरे साथी जहां झज्जर का जिक्र कर रहे थे, झज्जर में ज्वाइंट वेंचर से प्लांट लगाया जा रहा है जो 2010 से पहले-पहले शुरू हो जायेगा। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पाये इसलिए मैं दोबारा से अपना सवाल पूछता हूँ। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वर्ष 2006 में बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई एम०ओ०यू० साईन किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे तो दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको बताया कि 2004-2005 में यमुनानगर में 600 मेगावट का जो प्लांट लगाया है वो नवम्बर 2007 तक चालू हो जायेगा। (घोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, यह पूछिये कि 40 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई और अगले 5 साल में कितनी प्रोडक्शन का प्लान है। इसमें सारी बातें आ जायेंगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये दरअसल कम्प्यूज्ड हो रहे हैं। यमुनानगर के अन्दर 600 मेगावट के प्लांट का हमने काम शुरू करवाया है और इसकी पहली यूनिट नवम्बर, 2007 तक तैयार हो जायेगी यह हमने जवाब में भी दे रखा है। जो दूसरी यूनिट है वह फरवरी, 2008 में तैयार हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारी टोटल कैपेस्टी जनरेशन की 1587.4 मेगावट है और टोटल एवलेबिलिटी 4051 मेगावट है लेकिन इस समय हमारे पास 70 परसेंट एवलेबल है। बिजली की कमी है और खास तौर पर जो पीक ऑवर हैं उस समय ज्यादा दिक्कत आती है। एक प्लांट हमने जनवरी, 2007 में हिसार में 1200 मेगावट का शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि इसकी पहली यूनिट दिसम्बर, 2009 में और दूसरी यूनिट मार्च, 2010 में चालू हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार से झज्जर में एक प्लांट लगाने का काम through complete bidding private sector को दिया है। जिसकी कैपेस्टी 750 मेगावट है। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मई या जून, 2007 में इसका अर्दाई भेजा जायेगा और यह 2010 तक शुरू हो जायेगा और तकरीबन 45 करोड़ रुपये का इसका बजट है। टोटल एवलेबिलिटी इन प्रोजेक्ट्स की इस प्रकार है: यमुनानगर का 600 मेगावट, हिसार का 1200 मेगावट, और झज्जर में NTPC का 750 मेगावट है। जिसमें हमारा ज्वायंट वेंचर है, इसमें दिल्ली के साथ, NTPC के साथ और हमारी 300 करोड़ रुपये की इक्विटी होगी। झज्जर का जो दूसरा हमारा पॉवर प्लांट है। उसकी 1200 मेगावट की क्षमता है। हिमाचल प्रदेश में बुढील के अन्दर एक प्राईवेट कंसर्न है जिसकी 70 मेगावट की क्षमता है और एक अमर कटक में भी प्राईवेट कंसर्न है जिसकी 300 मेगावट की क्षमता है। इस प्रकार हमारी टोटल पॉवर क्षमता जो है वो 5000 मेगावट हो जाएगी। इस तरह से हम 4720 मेगावट बिजली प्रदान कर सकेंगे। जो गैस बेस्ड प्लांट है जिसके बारे में आप जिज्ञास कर रहे थे। वो हम फरीदाबाद में सैटअप कर रहे हैं और यह पूरा गैस की उपलब्धता पर निर्भर है। जैसे कि आप जानते हैं कि गैस की उपलब्धता की कमी है। उसके लिए हमने 6 सितम्बर 2005 को जिन्दल स्टेनलेस लि० हिसार और गेल के साथ 1080 मेगावट की उपलब्धता के लिए हैड ऑफ एग्रीमेंट साईन किया है और यह हमारी आई०पी०पी० (इन्डिपेन्डेंट पावर प्रोजेक्ट) की प्रोजेक्ट साईट है। इसी प्रकार से 16 सितम्बर, 2005 को मै० विजमैन प्राईवेट लिमिटेड मुंबई विद गेल जिसकी प्रोजेक्ट साईट पानीपत में है उसके साथ 600 मेगावट की उपलब्धता के लिए हैड ऑफ एग्रीमेंट साईन किया है। इसी प्रकार 14 अक्टूबर, 2005 को मै० तायल एनर्जी सिलवासा विद गेल जिसकी प्रोजेक्ट साईट पानीपत है उनके साथ 400 मेगावट की उपलब्धता के लिए हैड ऑफ

एग्जीमेंट साईन किया है। इसी तरह मै० टाटा पॉवर कम्पनी विद गेल जिसकी प्रोपोज्ड साईट झज्जर है उसके साथ 1000 मेगावट के लिए हैड ऑफ एग्जीमेंट साईन किया है। इसी प्रकार मैसर्स ऐबन लॉयड ऑफ शोर लिमिटेड, चेन्नई, के साथ भी एग्जीमेंट साईन किया हुआ है। फरीदाबाद जिसके बारे में ये जिक्र कर रहे थे उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब यह एग्जीमेंट साईन किए गए उस समय गोदावरी में और राजस्थान में कुछ जगहों पर गैस निकली थी उस वक्त यह उम्मीद थी कि गैस की एवलेबिलिटी काफी हो जाएगी और उसको सोचते हुए विद गेल तीन मई, 2005 को फरीदाबाद के अन्दर एक एम०ओ०यू० साईन किया गया। अध्यक्ष महोदय, गैस की अनसर्टेनिटी है और जब भी हमें गैस उपलब्ध हो जाएगी तो हमारे ये प्लांटस भी शुरू हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा न्यूक्लीय प्लांट के बारे में मैंने जिक्र किया था जिसको लगाने के लिए माननीय प्रधान मन्त्री जी को रिक्वेस्ट की हुई है और हमारी सरकार इस 2800 मेगावट न्यूक्लीय पावर प्लांट को डिस्ट्रिक्ट फलेहाबाद में लगाने के बारे में भी विचार कर रही है। यह अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का है। इस तरह हमें करीब चार हजार मेगावट बिजली मिल पाएगी, 1400 मेगावट पावर फरोम यू०एम०पी०पी० मुन्द्रा से, 400 मेगावट, सासन से, 450 मेगावट उड़ीसा से और झारखण्ड से 200 मेगावट के साथ साईन किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो सक्सैफुल बिडरज हैं उनके साथ भी हमने 9-10-2006 को परन्नेज एग्जीमेंट किए हैं। हम हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लीय पावर और गैस बेस्ड पॉवर के लिए जो कम्पनीज बिडरज हैं और जिनकी क्षमता 2000 मेगावट की है उन कम्पनीज से टैरिफ इन्चार्ज किए हैं जिससे प्रोजेक्ट करीबन 2000 मेगावट की होगी। इसके लिए 14 बिडरज ने क्वालीफाई किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य किया है, हालांकि चौटाला साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इन्होंने 210 मेगावट यूनिट का उत्पादन किया, उसके अलावा पांच साल में केवल घोषणाएं ही की हैं, पत्थर लगा दिया और केवल किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी। इनकी सरकार ने किया कुछ नहीं लेकिन हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उससे अब इनकी तसल्ली हो गई होगी। (विध्व)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का जबाब डिटेल् में नहीं आया है। जिस तरह से मन्त्री महोदय ने कहा है कि पिछली सरकारों के समय में सिर्फ घोषणाएं ही हुईं और कोई काम नहीं हुआ यह ठीक बात नहीं है। कल एक सवाल के जवाब में इन्होंने यह एसेप्ट किया कि बिजली पैदा नहीं हुई और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी माना कि हमने अभी तक एक भी मेगावट बिजली पैदा नहीं की है और अभी नये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आप मेरी बात सुनें हाउस में ही यह बात आई थी कि क्या दुनिया में कोई ऐसा थर्मल प्लांट है जिसने अढ़ाई साल से पहले बिजली की जेनरेशन शुरू कर दी हो। यह बात तो तीन दिन पहले ही आ गई थी। सदन के नेता खुद यहां पर यह बात कही थी कि थर्मल पावर प्लांट से जेनरेशन अढ़ाई-तीन साल से पहले नहीं आ सकती। (विध्व)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, डॉ. इन्दौरा साहब ने कहा है कि कोई बिजली पैदा नहीं की गई, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है लेकिन जितनी बिजली उपलब्ध थी और किसानों के लिए और बिजली की कमी पूरी करने के लिए हमने जितनी बिजली खरीदी इनके शासन के समय जितना पैसा खर्च किया गया था किसानों के लिए बिजली बाहर से खरीदने के लिए, उससे

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हमने डेढ़-दो गुणा तक ज्यादा पैसा खर्च किया है। दूसरे आम दुनिया के किसी भी एरिये का नाम बता दो कि कोल बेस्ड बिजली का प्लांट दो साल में तैयार हो गया हो। हमारे यहाँ पर नवम्बर में अढ़ाई साल में बिजली बननी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 2009-10 तक गैस बेस्ड प्लांट पर 17 हजार 4 शौ करोड़ इन्वेस्ट होगा और परचेज एग्रीमेंट के द्वारा 4720 मेगावट बिजली अवेलेबल होगी। इसके अलावा पेटका की चर्चा की है, इसके लिए 2000 मेगावट के लिए कम्पीटेटिव थ्रीडिन्स इन्वाइट कर रखी हैं। हमें उससे और भी बिजली पैदा होने की उम्मीद है। अगर हम पिछले सालों से मुकाबला करें तो 7 प्रतिशत ज्यादा बिजली हमने पिछले साल दी है और पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष हमने 8 प्रतिशत ज्यादा बिजली दी है। हमने लगभग 18 प्रतिशत ज्यादा बिजली अब तक पिछले सालों के मुकाबले में दी है। स्पीकर सर, यह विपक्ष के लोग लोगों को भड़का कर गए थे और बिजली का वसीयतनामा दे गए थे कि बिजली के बिल मत भरो, यह नहीं करो और वह नहीं करो हमने आते ही बिजली की जो समस्या थी उसका समाधान निकाला है।

Opening of Government or Private Medical College in Faridabad

*606. Sh. Mahender Partap Singh : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government or Private Medical College in Faridabad city; and

(b) if so, the time limit by which the said college is likely to be opened?

स्वास्थ्य मन्त्री : (बहिन करतार देवी) :

(क) नहीं जी

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय भाई महेन्द्र प्रताप सिंह जी को यह भी बताना चाहूंगी कि इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से शिक्षा में काफी उदारता बरती गई है उसी तरह से चिकित्सा शिक्षा में भी सरकार ने काफी उदारता बरती है। अगर कोई संस्था ऐसा प्रस्ताव लेकर माननीय साक्षी के पास आई है तो मैं इस बारे में इनको बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार एन.ओ.सी. देती है। अगर वह संस्था नार्मल पूरे करती होगी तो हमें उसको एन.ओ.सी. देने में कोई एतराज नहीं है लेकिन अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हाँ, एक डेंटल कालेज का प्रस्ताव आया था जोकि फरीदाबाद में चालू हो गया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने भी चट्टा साहब की तरह जवाब दे दिया कि सवाल पैदा ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने चट्टा साहब के सवाल के जवाब में अपनी तरफ से जवाब देकर एक उम्मीद जगा दी कि उस पर काम होगा।

श्री अध्यक्ष : यह अलग डिपार्टमेंट था और यह अलग डिपार्टमेंट है। महेन्द्र प्रताप जी अगर आपकी नोलेज में कोई प्रस्ताव है तो आप बताएं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से जो बहुत ही फ्राख दिल के व्यक्ति हैं, विनम्र आग्रह के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि फरीदाबाद की यह भाग आज की नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी है। इस भाग के उपर यही कहा जाता रहा है कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या आपकी तरफ से या फरीदाबाद जिले के एम०एल०एज० की तरफ से मंत्री जी को इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा गया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर सर, हमने सरकार को मैमोरैण्डम दिया है और उस पर सब कुछ लिखा है। उस बारे में मुख्यमंत्री जी ने वायदा तो नहीं किया था लेकिन यह कहा था कि उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि फरीदाबाद आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा जिला है। 2-3 जिलों के बराबर इन्डस्ट्रीयल एरिया है। यह इन्डस्ट्रीयल एरिया स्टेट को बहुत बड़ा एक्सटेंड कर देता है। एक्सपोर्ट में भी राष्ट्र को बहुत बड़ा योगदान देता है। यह भाग वहां की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही फ्राख दिल व्यक्ति है और इन्होंने प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि इस आवश्यकता और न्यायोचित भाग को देखते हुए जनता की उन्नति के लिए इस पर सहानुभूति से गौर करते हुए, इस पर विचार करके, इस भाग को पूरा करें।

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगी कि हमारी स्टेट में तीन मेडिकल कालेज हैं जिनमें से एक रोहतक मेडिकल कालेज है जिसको पी०जी०आई० का दर्जा दे दिया गया है। एक मेडिकल कालेज अग्रोहा में गवर्नमेंट एडिड है। प्राइवेट सेक्टर में केवल मुलाना में मेडिकल कालेज है। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूँ कि यदि कोई प्राइवेट संस्था इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आती है तो सरकार को उसको एन०ओ०सी० देने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ब्रीफिंग के टाईम पर भी मुख्यमंत्री जी ने यह उदारता दिखायी थी कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो हम उस पर सहानुभूति ही नहीं दिखाएंगे बल्कि उसको क्रियान्वित करने के लिए भी उस पर विचार भी किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र में तो अभी केवल वह प्रस्ताव ही विचाराधीन है जिसकी प्रधानमंत्री जी ने पानीपत के अंदर कल्पना चावला की स्मृति में मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की थी। इस बारे में नासा से बातचीत चल रही है उसके क्लीयर होने के बाद ही करनाल में मेडिकल कालेज स्थापित होने की संभावना है। स्पीकर सर, अभी फरीदाबाद के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझती हूँ लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हाउस में केवल वहीं आश्वासन देना चाहिए जिसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। इसलिए मैं अपने भाई से कहना चाहती हूँ कि वे अभी थोड़ा सा इंतजार करें या वे कोई ऐसी संस्था तलाश करें जो यह काम कर सकती हो। उसके बाद ही पूरी सहानुभूति के साथ ऐसे प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का हम प्रयास कर सकते हैं।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, भिवानी का जो सिविल होस्पिटल है वह एशिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा होस्पिटल है। इसमें स्किन, मेडिसिन, सर्जरी, ई०एन०टी० और

[डॉ० शिव शंकर भारद्वाज]

आईज जैसे सब विभाग कार्यरत हैं इसलिए इसको मैडिकल कालेज बनाने में सरकार पर अधिक बोझ भी नहीं आएगा और साथ ही मैडीकल कालेज बनने पर यह सारे दक्षिणी हरियाणा की मांग को भी पूरा करने में सक्षम हो सकता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जब वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो क्या सरकार उस सिविल होस्पिटल को मैडीकल कालेज बनाने पर विचार करेगी क्योंकि इससे सरकार को कोई ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप स्पैसिफिक सवाल पूछें। आपका सवाल हो लिया है। आपका सवाल बड़ी था कि क्या भिवानी के सिविल होस्पिटल को मैडीकल कालेज का दर्जा दिया जाएगा या नहीं ? आपका सवाल हो गया है इसलिए अब आप बैठें।

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, अभी तक तो इस बारे में कोई विचार नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य भाई रणबीर सिंह महेन्द्रा जी ने जो सवाल पूछा था उसके संबंध में ही मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हम उस होस्पिटल में क्वार्टर थैरपी का एक केंसर यूनिट खोलने जा रहे हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बहिन जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि फरीदाबाद में होस्पिटल बनाने के लिए इतना ज्यादा पैसा लगाने वाली पार्टी को तो केवल दलाल साहब ही लेकर आ सकते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरे नोटिस में कोई इस तरह की पार्टी नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट वहां पर कौन करना चाहेगा ?

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र प्रताप जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आ लिया है, आप बैठें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर सर, मैडीकल कालेज फरीदाबाद जिले की आबादी की दृष्टि से भी जरूरी है। इस समय वहां के होस्पिटल में एम०आर०आई० की भी सुविधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप बैठें। आप बहिन जी के आफिस में जाकर इस बारे में रिक्वेस्ट कर लेना! You are repeating the same thing again and again. आपका सवाल हो गया है, अब आप बैठें। कल पालियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बताया था कि फरीदाबाद को जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्थूवल मिशन के तहत कवर किया गया है इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका जिला नेशनल स्कीम में कवर हो गया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या उसमें पैसे की व्यवस्था हो सकेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह दो हजार छः सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, स्वास्थ्य सरकार की बहुत बड़ी चिन्ता है और हमारी सरकार ने होस्पिटल के लिहाज से बहुत सारी सुविधाएं भी प्रान्त में दी हैं। प्रदेश में प्राइवेट होस्पिटल भी बहुत ज्यादा पनपे हैं और इन प्राइवेट होस्पिटल के अंदर मरीजों के इलाज के लिए बेशुमार पैसा लिया जाता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदया बताएंगी कि इन प्राइवेट होस्पिटल में गरीब व्यक्तियों के उपचार के लिए इनकी फीस कंट्रोल करने का कोई विचार है ?

10.00 Mr. Speaker : Chhattar Pal Ji, this question is pertaining question to the Government Medical Colleges or private Medical Colleges. You ask separate question.

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे हल्के छछरीली में भी कोई अस्पताल खोलना सरकार के विचाराधीन है ? वहाँ भी लोग बीमार होते हैं और वहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ फ़र्स्ट ऐड वगैरह मिल जाए। जगाधरी और कलेसर के बीच में 40 किलोमीटर का फाँसला है। किसी पेशेन्ट को वहाँ ले जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको जगाधरी ले जाओ। जगाधरी ले जाने तक तो वह भगवान के घर ही पहुँच जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या छछरीली में कोई अस्पताल खोलना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : यह मेडिकल कॉलेज से परटेन करता सवाल है।

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, वैसे तो माननीय सदस्य अरजन सिंह का सवाल इस सवाल से परटेन नहीं करता है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अस्पताल बनाने के नॉर्मस भारत सरकार बनाती है। उसके हिसाब से पाँच हजार की आबादी पर एक सैन्टर, 20-25 हजार की आबादी पर पी०एच०सी० और 1 लाख 20 हजार की आबादी पर सी०एच०सी० बनाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अस्पताल बनाए जाते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ देश के बहुत सारे प्रदेशों से आगे हैं। 1991 की जनगणना के मुताबिक नयी पी०एच०सी० हम बनाएंगे। माननीय सदस्य अपने यहाँ कहीं जमीन की सिचुरेशन देखकर बताएं और कोई प्रस्ताव इस बारे में लिखित में भेजें तो उस पर विचार किया जा सकता है। (विध्वन)

श्री अध्यक्ष : अरजन सिंह जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना कि आपके यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्राइटेरिया है और क्या वह क्राइटेरिया भीटआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको देखकर माननीय मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगी।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है। कोई भी सरकार हो, स्वास्थ्य सुविधायें देना हर सरकार की जिम्मेदारी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के कितने पद खाली हैं और वे पद कब तक भरे जाएंगे ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, वैसे तो माननीय सदस्य पलाका जी का सवाल इस सवाल से परटेन नहीं करता है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि पिछले दिनों डॉक्टरों की भर्ती की गई थी और काफी पद भरे गए थे। लेकिन देहाती इलाकों में आज भी डॉक्टरों के पद कई जगह खाली हैं। 123 पदों की मंजूरी एस०एस०सी० से आ चुकी है और उनको अपॉइंटमेंट देने का काम हम कर रहे हैं। जब मैंने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला था उस समय डॉक्टरों की, स्टाफ नर्सिज की, रेडियोलॉजिस्ट की कमी थी, हर चीज की कमी थी। इस सरकार ने आते ही पदों को भरने का पूरा प्रयास किया है।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, विभाग सभा में मैं इस बारे में बहुत बार मांग कर चुका हूँ और पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर साहब मेरे हल्के के बास गाँव में गए थे। मेरे हल्के में तीन

[श्री राम कुमार गौतम]

बड़े बड़े गांव हैं उनमें से बास बहुत बड़ा गांव है जिसकी चार पंचायतें हैं। वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बास गांव के आस-पास बहुत सारे गांव हैं। इस गांव में डॉक्टर अप्वांचंट कर देने से आसपास के गांवों को भी सुविधा हो जाएगी। इस बारे में कई बार मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से रिक्वेस्ट की जा चुकी है। क्या थोड़ी ठण्डी नजर उस इलाके की और भी करेंगे क्योंकि बास गांव में कोई डॉक्टर नहीं है और मरीजों को जीन्द, हिसार, भिवानी या रोहतक जाना पड़ता है।

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, माननीय सदस्यों को मैंने पहले भी बताया है कि डाक्टरों की लिस्ट एस०एस०सी० से आ गई है और जल्दी से जल्दी उन डाक्टरों की पोस्टिंग कर दी जायेगी और जहां पर पोस्ट खाली हैं वहीं पर डाक्टर लगाये जायेंगे। लेकिन एक बात सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे की कोई भी डाक्टर देहात के इलाके में रहने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उनकी पोस्टिंग करती है लेकिन कोई न कोई माननीय सदस्य फिर उनकी पोस्टिंग शहर में करने के लिए कह देता है।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, ऐसे डाक्टरों की लिस्ट मंत्री जी को दे दें जो गांव में रहना चाहते हैं।

बहिन करतार देवी : इसलिए सभी माननीय सदस्यों द्वारा डाक्टरों को समझाना चाहिए कि उनकी सेवा की जरूरत शहर की बजाए गांव में ज्यादा है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अभी मंत्री महोदय ने असेप्ट किया है कि करनाल में सरकार मैडीकल कालेज खोलने जा रही है और प्राइवेट मैडीकल कालेज और होस्पिटल खोले जा सकते हैं। जिस प्रकार दिल्ली में प्राइवेट होस्पिटल जैसे अपोलो और राजीव गान्धी अस्पताल हैं लेकिन इन अस्पतालों में गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था या कोई छूट नहीं है। इसी प्रकार गुड़गांव में डाक्टर ब्रेहन द्वारा एक प्राइवेट अस्पताल खोला जा रहा है क्या उस अस्पताल में दक्षिणी हरियाणा या आस-पास के गांवों के गरीब मरीजों के लिए कोई स्पेशल रियायत या कोई सुविधा दी जायेगी? कृपया मंत्री जी इस बारे में विस्तार से बतायें।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूँ कि करनाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि नासा की मदद से कल्पना चावला के नाम से एक मैडीकल कालेज खोला जायेगा। इस विषय में हरियाणा सरकार की नासा के साथ बातचीत चल रही है और उनके सहयोग से ही यह मैडीकल कालेज वहां पर खोला जायेगा।

Tenders for Construction of Roads/Buildings in H.S.A.M.B.

*619. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that tenders for construction of roads and buildings have been invited/awarded at Panchkula in Haryana State Agricultural Marketing Board; if so, the details thereof?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, a statement is placed on the table of the house.

STATEMENT

Tenders for Construction of Road and Buildings are invited at Panchkula only in those cases where administrative approval of the work is more than Rs. 25.00 lacs. The detail of the tenders year wise awarded by the H.S.A.M. Board at Panchkula is as under :

S. No.	Description of item	Year 2004-2005	Tentative Amount in Lacs	Year 2005-2006	Tentative Amount in Lacs	Year 2006-2007	Tentative Amount in Lacs
1.	New Link Roads	50 Nos.	1402.45	42 Nos.	1788.77	88 Nos.	3961.36
2.	Special Repair of Link Roads	87 Nos.	1594.00	25 Nos.	2922.90	40 Nos.	5200.24
3.	Mandi Works.	54 Nos.	2049.33	34 Nos.	2097.60	121 Nos.	9614.44
4.	Total	191 Nos.	5145.78	101 Nos.	6809.27	249 Nos.	18776.04

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखी है वह दर्शाती है कि बहुत बड़ा बजट हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा ग्रामीण सड़कों, मण्डियों और नई सड़कों की रिपेयर पर खर्च किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह जानते हैं कि जो मार्केटिंग बोर्ड के जो रोडज हैं या मण्डी बनाने की जो इनके बोर्ड की विंग है वह पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर०) की तर्ज पर बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, बी०एण्डआर० विभाग में अब जो सड़कें या भवन बनते हैं उनके जो टैण्डर लेने का तरीका है वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विभाग के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए कम्प्यूटराईज करने का प्रावधान किया है जबकि पिछली सरकार के समय में टैण्डर बन्दूक की नोक पर या उनके हुकूम पर दिए जाते थे, अब वह व्यवस्था सरकार ने समाप्त कर दी है और ईमानदारी की नयी रिवायत प्रदेश के अन्दर कायम की है उससे प्रदेश के लोगों का बड़ा मला हो रहा है। क्या मार्केटिंग बोर्ड में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय वही सिस्टम लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाये जाने वाली सड़कें और भवनों के कार्य ज्यादा देर तक लम्बित न रहें और लोगों को टैण्डर के लिए पंचकुला में धक्के न खाने पड़ें। 25 लाख रुपये की राशि बहुत कम राशि है इस राशि को बढ़ाकर एक करोड़ तक कर देना चाहिए और एक्सिशन और एस०ई० लेवल तक यह पावर दे दी जाए कि इतने अमाउंट तक के टैण्डर वे अपने स्तर पर इन्वाइंट कर सकें। क्या इस बारे में मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

सरदार एच०एस० चट्टा : स्पीकर साहब, पुरानी सरकार के समय में नीचे के लेवल पर रोब ब बंदूक की नोक से टैण्डर लिये जाने लगे थे। हमारी सरकार आने के बाद सिस्टम बदल दिया कि हर टैण्डर इन्वाइंट तो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर करेंगे और पांच लाख रुपये तक के टैण्डर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर खोलेंगे। उसके बाद 20 लाख रुपये तक के टैण्डर एस०सी० दफ्तर में

[सरदार एच०एस० चट्टा]

खुलेंगे। और उससे थड़ी अमार्ड के जो टैण्डर होंगे उनको खोलने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के तीन बड़े अधिकारियों की कमेटी बना दी गई जो हैड आफिस में उनके सामने खोले जायेंगे। पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एंड आर०) विभाग में भी इसी तरह की कमेटी बनी हुई है। स्पीकर साहब, हम नहीं चाहते कि बड़े-बड़े टैण्डर लोअर लेवल पर खोले जायें और लोगों के साथ धोखाशाही होती रहे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मार्केटिंग बोर्ड का सिविल विंग पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) विभाग की तर्ज पर ही है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) विभाग में टैण्डर लिये जाते हैं उसी तर्ज पर मार्केटिंग बोर्ड में भी टैण्डर लिये जायें क्योंकि मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशों मुताबिक अब प्रदेश में लूट-खसूट बन्द हो चुकी है और हैड-क्वाटर पर लोगों को आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है तथा दूसरा कारण यह भी है कि बड़े टैण्डर हैड-क्वाटर पर अलोट होने से काम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पलवल में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा पैसा दिया लेकिन वहाँ जो काम हुआ उसकी क्वालिटी ठीक नहीं आई। क्या उसकी जांच कराकर जिन्होंने ठीक काम नहीं किया उनसे रिकवरी की जायेगी और टैण्डर पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्डआर०) विभाग की तरह से भविष्य में अलोट किए जायेंगे ?

सरदार एच०एस० चट्टा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का सवाल जलेबी की तरह हो गया है। माननीय साथी का पहला सवाल यह है कि टैण्डर सिस्टम कैसा होना चाहिए और दूसरा सवाल काम में हेराफेरी का है कि काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। यदि माननीय साथी को कहीं पर काम ठीक न होने की शिकायत है तो उसके बारे में ये अलग से नोटिस दे दें उस पर तुरन्त इन्क्वायरी करवाई जायेगी। जहाँ तक टैण्डर अलोट करने की बात है मैंने as a Agriculture Minister मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक यह फैसला लिया हुआ है जैसा मैंने अपने जवाब में बताया है कि बड़े टैण्डर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियरों के हवाले नहीं किए जायेंगे और बड़े टैण्डर हैड आफिस में ही खोले जायेंगे। स्पीकर साहब, एक बिजनस मैन को यहाँ आने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक बड़ा सूबा नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक बड़े टैण्डर यहाँ पर बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने ही खोले जायेंगे।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल साहब ने एक प्रश्न पर चर्चा की है। मेरे सामने विपक्ष के मेरे काबिल दोस्त बैठे हुए हैं। इनके उस्ताद का राज था। उस वक्त सभी टैण्डर की अलौटमेंट में अनियमितताएं हुईं। (विघ्न) इसलिए मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि उस वक्त एक व्यक्ति विशेष को सारे मनमाने भाव पर दिए जाते थे और उसकी कुछ राशि इनके उस्ताद की जेब में चली जाती थी। क्या हमारी सरकार के सामने इस तरह के कोई पुराने केस आये हैं कि टैण्डर देने में घपले हुए हों और किसी से कोई रिकवरी हुई है।

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी का शुक्रियादा करता हूँ कि इसके लिए हमारा सिस्टम बहुत हाई है और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बारे में ये किसी से एक छोटी सी कम्प्लेंट दिला दें उस पर असर गोली की तरह होगा। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत ही अहम सवाल, प्रोसेस सिस्टम का किया है इस बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ कहना भी चाहूँगा और कुछ

जानना भी चाहूंगा। बड़े टेण्डरों और इस करप्शन को रोकने के लिए, वहां जो मिली भगत होती है उसको चेक किया जाना चाहिए। ये जो प्रोसेस सिस्टम कायम किया है इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रोसेस सिस्टम का सरलीकरण किया जाये। सरलीकरण न होने की वजह से 2005 में जो सड़कें सैंक्शन की गई थी, 2007 तक वो सड़कें कम्पलीट नहीं हो पाई हैं और एक-एक ठेकेदार को 25-25 सड़कों का ठेका दे दिया जाता है एक जिले की सभी सड़कों का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया जाता है जिससे कोई भी सड़क समय पर तैयार नहीं हो पाती। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मुद्दा है कि सरकार की नीयत ठीक है और बजट की कमी नहीं है तो फिर बजट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस प्रोसेस सिस्टम का सरलीकरण किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए। एक प्रश्न के लिए 3 मिनट का समय रखा गया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था में कैसे एक-एक व्यक्ति को 4-4 जिलों के ठेके दे दिये जाते हैं और जो सड़कें हैं वे अब तक नहीं बनी हैं। दो साल में क्यों नहीं बनी उनकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी जो सड़कें बनी हैं वे भी सभी उखड़ने लगी हैं, उनके अन्दर सब-स्टैंडर्ड मैटीरियल लगाया गया है क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे।

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं रिस्पेक्टिड मैम्बर को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये कम्पलेंट करेंगे तो हम उसकी जांच करवाएंगे। मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिया हुआ है कि यह कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों को कारपेट किया जाए, सड़कों पर त्रोंपे न लगाए जाएं। छोटा-छोटा करके रिपेयर का काम न किया जाए। कई ठेकेदारों के पास साधन होते हैं लेकिन छोटे ठेकेदारों के पास ज्यादा साधन नहीं होते हैं। बड़े ठेकेदारों को ज्यादा काम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके पास काम करने का साधन है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको किसी पर कोई शक है तो ये लिख कर दे दें हम इन्कवायरी करवा लेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि कई लोगों को टेण्डरज अलॉट किये जाते हैं और विद इन टाइम पीरियड अगर वे कार्य नहीं करते तो क्या उन पर पैनल्टी डाली जाती है? (विघ्न)

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में क्या होता था क्या नहीं होता था वह तो सारे सूबे ने बतल दिया है और ये यहां पर गिने-थुने ही रह गये हैं। जहां तक हमारी सरकार की बात है, जो ठेकेदार वक्त पर काम नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उस पर इर्जाना भी डाला जाता है। अगर नौबत बढ़ जाए तो उसको ब्लैक-लिस्ट भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मुख्य मंत्री के होते हुए इनको चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर सर, मैं भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सड़कों के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे हल्के में तीन सड़कें दो साल से बन रही हैं। (विघ्न) पिछली सरकार का तो जिक्र ही मत छोड़ा करें क्योंकि पिछली सरकार में तो घ का घ बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। च से मतलब थोटाला साहब और घ से मतलब घोटाला करना था और कोई इसका मतलब नहीं था। (हंसी) पिछली सरकार का जिक्र मत किया करो वे तो ट्रेनिंग ही एक दिया करते

[श्री० अर्जुन सिंह]

थे। स्पीकर सर, मेरी दो सड़कें हैं सज्जाद पुर से पान्सरा, शेरपुर दू डारपुर और तीसरी रोड है सहारनपुर रोड ये तीनों की तीनों सड़कों की कोई गौर नहीं हुई है। थोड़े समय तक दो चार दिन उस पर काम होता है और उसके बाद काम फिर बन्द हो जाता है।

सरदार एच०एस० चट्टा : स्पीकर सर, मैं हाउस के सामने ही अपने ऑफिसर को आदेश देता हूँ कि यदि ये सड़कें मेरे महकमें के तहत आती हैं तो इन सड़कों का कार्य तुरन्त शुरू किया जाए और इनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए।

श्री अमीर चन्द भवसूड : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दाणी पाल से शेरपुरा तक सड़क बनाने का टैण्डर पिछले साल हो गया था। लेकिन अब तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। क्या जल्दी ही उस सड़क का काम करवाएंगे। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड की कुछ सड़कें हैं।

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह अनुरोध करता हूँ कि ये मुझे अपनी सड़कों के बारे में लिख कर दे दें अगर वे सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की हैं तो वे धनशः दी जाएंगी और उन सड़कों पर गाड़ियां इतनी तेजी से दौड़ेगी जैसे हाई-वे पर दौड़ती हैं।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले में मार्केटिंग बोर्ड की 25 सड़कों का गोपाल जी एण्ड कम्पनी को ठेका दिया है। छः महीने का इन सड़कों को बनाने का टाईम था इनमें से छः सड़कें ऐसी हैं जो दो साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कम्पलीट नहीं हुई हैं, क्या उनको कम्पलीट करवाएंगे ?

सरदार एच.एस. चट्टा : अध्यक्ष महोदय, न तो मैं कम्प्यूटर हूँ और न ही मुझे हर बात जुबानी याद है। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में लिख कर दे दें या अगले सेशन में सवाल पूछ लें।

कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो श्री उदय भान जी ने कहा है कि गोपाल एण्ड कम्पनी है या गोपाला एण्ड कम्पनी है, ये चौटाला जी के आदमी हैं उनको पहले भी ठेके देते थे और अब भी दिये गये लेकिन वे कोई काम नहीं करते हैं। क्या मन्त्री महोदय उनकी जांच करवाएंगे कि जो गोपाला एण्ड कम्पनी पलवल और फरीदाबाद में है क्या यह वही कम्पनी है ?

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यदि कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। (विष्णु) जहाँ तक जांच करवाने की बात है, मुझे लिख कर दे दें मैं उसकी जांच करवा दूंगा।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे साल्हावास विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर रेलवे स्टेशन कोसली से जुड़डी को जो मार्केटिंग बोर्ड की रोड जा रही है और दूसरी नाहड़ से नेहरु गढ़ की तरफ जो सड़क जा रही है एक पर तो रोड भी नहीं डले और दूसरे का टैण्डर लगभग दो साल यानि अपनी सरकार आने के बाद हो चुका है लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ। स्पीकर सर, ऐसी और भी कई छोटी-छोटी सड़कें हैं जिन पर मुरम्मत का काम भी नहीं हुआ है और पैदल चलने लायक भी नहीं हैं। क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि इन सड़कों का काम कब तक करवा देंगे ?

सरदार एच०एस० चट्टा : स्पीकर सर, बहिन जी ने जो बात कही है वह मुझे याद नहीं है और न ही मैंने वह जगह देखी हुई है। इनको जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बहिन जी, आप इनको बता देना या सैपरेट नोटिस दे देना क्योंकि यह वाइडली डिस्कस हो गया है।

Completion of Narnaund-Sulchani Road by HSAMB

*664. **Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct/complete the Narnaund-Sulchani Road by the Haryana State Agricultural Marketing Board ?

कृषि मंत्री (सरदार एच.एस. चट्टा) : हाँ श्रीमान जी,

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सड़क को बने हुए 5 साल हो गए हैं लेकिन चालू नहीं हुई है। यह सड़क दोनों तरफ से तो बन चुकी है लेकिन बीच में लगभग 500 मीटर का टुकड़ा है जो बना हुआ नहीं है जिसकी वजह से यह सड़क चालू नहीं हुई है। क्या मंत्री जी उस टुकड़े को बनवाकर सड़क को शुरू करवाने का काम करेंगे ?

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल सही है कि वह सड़क दो तरफ से तो बन गई है लेकिन बीच में 489 मीटर का टुकड़ा है जो बना नहीं है। यह सब पिछली सरकार के वक़्त में हुआ था। उन्होंने ऐसी मेहरबानी की थी कि दफा चार तो लगा दी लेकिन उसके बाद दफा 6 नहीं लगाई, जिसके तहत जमीन एक्वायर करनी होती है जिसकी वजह से यह टुकड़ा बन नहीं पाया था। लेकिन अब वहाँ पर दफा 6 लोनी है। वे आदमी उस जमीन को देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। माननीय साथी हमें उनसे चिढ़ी दिलवा दो और उस जमीन पर कब्जा करवा दो तो हम उस सड़क को अगले सेशन से पहले बनवा देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गौतम जी को कहना चाहूँगा कि जमीन का पोजीशन मिलने के बाद हम 6 महीने में वह सड़क बनवा देंगे।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सैक्शन 4 और सैक्शन 6 लगाने में कितना समय लगेगा ?

सरदार एच०एस० चट्टा : स्पीकर सर, अगर यह समय की बात करते हैं तो सुनें। वहाँ पर हमने दफा 4 कर दी है। उसके बाद दफा 6 लागू होगी। उसके बाद जब जमीन की प्लैन्ट हो जाएगी, फिर हम कब्जा लेंगे। उसके बाद ही वहाँ पर सड़क बन जाएगी और इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको कह दिया है कि आप उनको हमारे पास लाओ, हमारे से पैसा लो और जमीन पर कब्जा दिलवा दो। उसके बाद हम वहाँ पर 6 महीने में सड़क बनवा देंगे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला महेन्द्रगढ़ में 2 साल से 3-4 रोडज के बारे में लिख कर दिया हुआ है। उन खराब सड़कों की वजह से वहां पर स्कूल का रास्ता रुका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक राता से मौलड़ा गांव की सड़क है, दूसरा भौकलपुर स्कूल बहुत पुराना है वहां पर अटेली बेगपुर से बिहाली तक रास्ता रुका हुआ है उस सड़क को रिपेयर करवाने की जरूरत है। इसी तरह से अकबरपुर से नांगलिया की सड़क है। वहां पर भी बस गिर गई थी जिसकी वजह से वहां पर आज भी खड़ा पड़ा हुआ है। आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि ये सड़कें जल्दी से जल्दी बनवाई जायें।

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, बर्खास्त होना चाहिए कि मेरे पास जो सवाल है उसी के बारे में प्रश्न पूछा जाना चाहिए क्योंकि मैं उसी का जवाब दे सकता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि सारे सूबे की सड़कों के बारे में याद रखूँ। माननीय सदस्य अपना प्रश्न मुझे लिखकर दे दें, मैं उस बारे में इनको उचित जवाब दे दूंगा।

श्री नरेश यादव : मंत्री जी, आप जिला महेन्द्रगढ़ में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई किन्हीं भी दो सड़कों के नाम बता दें।

सरदार एच.एस. चट्टा : आप यह सवाल भी लिख कर दे दें मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मार्केटिंग बोर्ड के अन्दर ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन पर कुछ पैसा खर्च हो चुका है और कुछ पैसे लगने के बाद वे सड़कें बर्किंग कंडीशन में आ जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि अगर उन सड़कों में कोई टैक्नीकल प्रोब्लम नहीं है तो उन सड़कों को प्रायोरिटी पर घुसा कर देना चाहिए। क्या मंत्री जी बताएंगे कि कितनी ऐसी सड़कें हैं और क्या मंत्री जी उनको प्रायोरिटी पर पूरा करवाएंगे, अन्यथा वह वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है।

सरदार एच०एस० चट्टा : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है I am thankful to him, मैं आपके माध्यम से इनको बलाना चाहूंगा कि मार्केटिंग बोर्ड की ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो अन-कम्पलीट हैं। जिन सड़कों के ऊपर अलाईनमेंट का, लैंड एक्वीजिशन का और कोई दूसरा झगड़ा नहीं चल रहा है। तो हम उन सड़कों को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाने की कोशिश करेंगे और उनमें कतई देरी नहीं करेंगे।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर सर, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा में पी०डब्ल्यू०डी० ने बहुत अच्छे काम किये हैं। लेकिन मार्केटिंग बोर्ड के अन्दर काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र में गादरा से खराबड़ और गादरा में अटायल मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं इनकी कोई रिपेयर नहीं हो रखी है। मंत्री जी कृपया इस ओर ध्यान दें।

सरदार एच०एस० चट्टा : आप आज मुझे लिखकर दे दें। आपकी सभी सड़कें रिपेयर हो जाएंगी।

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक साल से गोहाना से खरखौदा रोड की बहुत बुरी हालत है क्या उसको ठीक करवाया जाएगा ?

सरदार एच०एस० चट्टा : आप यह बताएं कि यह सड़क पी०डब्ल्यू०डी० की है या मार्किटिंग बोर्ड की है।

Mr. Speaker : Now, the Questions Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर

Imposing Ban on Manufacturing and use of Poly Bags

*Sh. Dharampal Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to impose ban on manufacturing and use of poly bags in the State to protect from pollution the soil contamination ; and
- (b) if so, the details thereof, togetherwith the time by which it is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस समय कोई विवरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। आवश्यक अधिसूचना दो महीनों में जारी की जानी संभावित है।

Azamgarh-Anta Canal

*692. Sh. S.S. Surjewala : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) the time by which Azamgarh-Anta Canal is likely to be completed;
- (b) the details of area which will be irrigated by this Canal; and
- (c) the details of distributaries and minors of said Canal ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हरियाणा में आजमगढ़-अंटा नहर नाम की कोई नहर नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

Amount Paid by Haryana Government as Old Age Pension

***663. Sh. Tejender Pal Singh Mann :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) the details of amount paid by Haryana Government as old age pension from 1-4-2006 to 31-12-2006 in the state ; and
- (b) whether the old age pension re-imbursed by the Government of India during the period referred to in part (a) above ; if so, the total amount of pension re-imbursed ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

- (क) श्रीमान जी, हरियाणा सरकार द्वारा 1-4-2006 से 31-12-2006 अवधि के दौरान 269.91 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था भत्ता के रूप में अदा की गई।
- (ख) जी हां, भारत सरकार द्वारा अब तक 1585.68 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

Sewerage System in Narnaund

***686. Ram Kumar Gautam :** will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay out the Sewerage System in Narnaund City ; if so, the time by which the Sewerage System is likely to be completed ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : जी हां, श्री मान जी। नारनांद शहर में सीवरेज प्रणाली बिछाने के लिये 291.60 लाख रुपये का अनुमान अनुमोदित किया गया है तथा 160.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की जा चुकी है। कार्य सम्पन्न होने की समय सीमा नहीं बलाई जा सकती क्योंकि माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों को स्टेट प्रदान किया हुआ है।

Repair/Remodelling of Water Courses

***695. Prof. Chhattar Pal Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

- (a) whether the Government has made provision for repair/remodelling of water courses of Bhakra/Yamuna Command Area alongwith the details of area falling in Ghirai Constituency ; and
- (b) up to what time these water courses are likely to be repaired ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

- (क) हां, श्री मान जी। घिराय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 42 जल मार्ग आते हैं जिनका कमान क्षेत्र 24170 एकड़ है उनकी मरम्मत का कार्य किया जाना है।
- (ख) सभी जल मार्गों की मरम्मत का कार्य आगामी 2 वर्ष की अवधि में पूरा किये जाने की संभावना है।

Vigilance Enquiry against Chairman/Members of H.P.S.C.

***620. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to**

state—

- (a) whether there is a vigilance enquiry pending against the Chairman/ Members of Haryana Public Service Commission ; and
(b) if so, latest position thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी के विरुद्ध सर्तकता विभाग में छः जांचे लम्बित हैं।

(ख) सूची संदन के पटल पर उपलब्ध है।

सूची

हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों एवं अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांचों की सूची।

क्र० सं०	जांच संख्या	विरुद्ध	आरोप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	जांच क्रमिक 3 दिनांक 21-4-05 चण्डीगढ़। मुकद्दमा नं० 20 दिनांक 18-10-05 जेर-धारा 420/467/468/471/120-बी०आई०पी०सी० एवं 13 अष्टाचार अधिनियम धाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार	श्री के० सी० बंधू, भूतपूर्व अध्यक्ष तथा श्री हरवीर सिंह सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग।	विभिन्न पद, जिनका विवरण नीचे दिया गया है के चयन में अनियमितता एवं धांधली। (i) एच०सी०एस० (कार्यकारी), तथा अन्य अलाइड सेवायें, परीक्षा 2004 (ii) प्राध्यापक (कालेज) वर्ष 2001 (iii) चौ० देवी लाल इंजिनियरिंग मैकेनिकल कालेज पन्नीवाला मोटा में प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक (iv) श्री के०सी० बांगड अध्यक्ष के कार्यकाल में अन्य विभिन्न पद।	हरियाणा लोक सेवा आयोग में न तो सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध करवाया और न ही जांच में सहयोग दिया, अतः इस मामले में मुकद्दमा नं० 20 दिनांक 18.10.05 धाना, रा० चौ० ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ने आयोग के सचिव को अनेक बार पत्र लिख कर रिकार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया है परन्तु आयोग द्वारा यह तक देकर कि वह रिकार्ड गम्भीर प्रकृति का है जिसे जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया है।

1	2	3	4	5
2.	जांच क्रमांक 4 दि० 26-4-05 घण्डीगढ़।	हरियाणा लोक सेवा आयोग व श्री ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से।	हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण अभियंता के चयन में अनियमितता करने बारे।	जांच में कुछ रिकार्ड प्राप्त कर लिया गया है पूर्ण रिकार्ड प्राप्त होते ही जांच को पूर्ण करके भेज दिया जायेगा।
3	जांच क्रमांक 16 दि० 7-10-05 घण्डीगढ़	हरियाणा लोक सेवा आयोग।	हरियाणा लोक सेवा आयोग विभिन्न महाविद्यालयों में थयनित प्राध्यापकों की परिष्कृत सूची नियत करने में अनियमिततायें करने बारे।	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्रमांक 1001/2005 में अपने आदेश दिनांक 29-8-2005 द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा को इस मामले की जांच 4 मास में करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिने थे। तत्पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7-11-2005 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश स्टे कर दिये।
4	जांच क्रमांक 12 दि० 23-10-06 घण्डीगढ़	हरियाणा लोक सेवा आयोग।	सलेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह की तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राध्यपक यान्त्रिकी के पद पर नियुक्ति में अनियमितता बारे।	श्री सलेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह शिक्षक आयोग द्वारा प्राध्यपक यान्त्रिकी के पद पर चयन किया गया था के आवेदन पत्र तथा उसके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि की भिन्नता थी। यह तथ्य विभाग के ध्यान में आया तत्पश्चात आयोग द्वारा इसकी सिफारिश वापिस लेने पर दिनांक 18-5-2006 को इसकी सेवार्थ समाप्त कर दी। इसके चयन के मामले की राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। कुछ रिकार्ड गोठाना, करनाल तथा सोनीपत से प्राप्त कर लिया गया है तथा सी०वी०एस०सी० से सम्बन्ध अजमेर (राजस्थान) से प्राप्त किया जाना है। जांच शीघ्र पूरी कर ली जायेगी।
5.	जांच क्रमांक 4 दि० 22-2-06 हिसार।	श्री धुद्धीर सिंह, सदस्य, हरियाणा लोक सेवा आयोग।	हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड में कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार से घन एकत्रित करना।	प्रियादायी के परिवार के बैंक खातों व अन्य सूचना एकत्रित की जा रही है।
6	जांच क्रमांक 1 दि० 16-5-05	श्री उरवीप सिंह, एच०सी०एस०	जाली रोल नम्बर देने के लिये 20	हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अभी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया है रिकार्ड

1	2	3	4	5
(बिस्फीट)	तत्कालीन सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग।	लाख रुपये की रिश्कत लेना।		प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Privatization of Bhuna Sugar Mill

***637. Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Bhuna Sugar Mill has been privatized; if so, the steps taken to adjust the employees of this Mill ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : परिसभापक द्वारा भूना सहकारी चीनी मिल मैसर्स वाहिद संघार शूगरज, फगवाड़ा को बेची गई है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पूर्व शर्त के साथ यह मिल बेची गई है कि खरीददार मिल के सभी कर्मचारियों को यथावत आधार पर रखेगा।

Repair of Roads

***696. Prof. Chhattar Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of Ghirai Constituency :—

1. Raipur to Sikarpur ;
2. Satroad Khurd to Ladwa;
3. Kharkeri to Ghirai;
4. Sulkhani to Rajli; and
5. Khokha to Kharkari;

if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : क्र० नं० 1, 2, 3, 4, तथा 5 हां, श्रीमान जी। इन सड़कों की मरम्मत को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान लिया जायेगा।

HRDF Scheme

***655. Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise details of total amount allocated/released and spent under the HRDF scheme during the financial year 2005-06 and 2006-07 to till date ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्री मान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

Statement

Statement showing District-wise Allocated/Released and Amount Spent under HRDF from 1-4-2005 to 28-2-2007

Sr. No.	Name of District	Amt. Allocated/Released	Amount Spent	Amt. Allocated/Released	Amount Spent	Amt. Allocated/Released	Amount Spent
		2005-06		2006-2007(Till 28-2-07)		Total (2005-2007)	
1.	Ambala	562.01	534.90	324.00	165.54	886.01	700.44
2.	Bhiwani	928.86	897.58	713.46	189.65	1642.32	1087.23
3.	Faridabad	818.05	712.45	770.39	219.71	1588.44	932.16
4.	Fatehabad	534.87	503.54	404.62	62.18	939.49	565.72
5.	Gurgaon	489.96	455.06	108.23	85.20	598.19	540.26
6.	Hisar	923.84	897.56	719.79	57.41	1643.63	954.97
7.	Jhajjar	1844.84	913.53	2146.23	235.97	3991.07	1149.50
8.	Jind	721.99	720.32	690.54	442.54	1412.53	1162.86
9.	Kaithal	937.44	920.80	625.35	139.51	1562.79	1060.31
10.	Karnal	381.18	334.03	316.82	107.11	698.00	441.14
11.	Kurukshetra	631.65	434.51	528.14	180.00	1159.79	614.51
12.	Mewat	436.38	182.75	337.93	260.84	774.31	443.59
13.	Mohindergarh	496.06	385.45	87.19	22.75	583.25	408.20
14.	Panchkula	231.77	208.25	107.94	14.26	339.71	222.51
15.	Panipat	412.92	366.74	333.08	114.11	746.00	480.85
16.	Rewari	689.75	576.04	479.38	63.17	1169.13	639.21
17.	Rohtak	2207.29	1837.77	2214.96	615.17	4422.25	2452.94
18.	Sirsa	467.43	390.43	265.46	63.96	732.89	454.39
19.	Sonepat	986.31	943.79	508.14	136.88	1494.45	1080.67
20.	Yamunanagar	498.74	403.85	359.53	175.35	858.27	579.20
District total		15201.34	12619.35	12041.18	3351.31	27242.52	15970.66
(in lacs)		15201.34	12619.35	12041.18	3351.31	17242.52	15970.66
(in crores)		152.01	126.19	120.41	33.51	272.43	159.71

अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

Investment made by the N.R. Is in the State

77. Dr. Sushil Indora : Will the Minister for Industries be pleased to state the details of number of youths employed by NRIs in the industrial sector in the State during the period from 1st April, 2005 to 31st December, 2006 ?

उद्योग मन्त्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) : श्री मान जी, राज्य में अनिवासी भारतीयों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान 605 युवकों को नियुक्त किया गया है।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the Hon'ble Chief Minister will make an obituary reference.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, 15 मार्च को हमारे एक साथी हमारे को छोड़कर चले गये हैं। मैं सदन में इस बारे में एक शोक प्रस्ताव लाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री जगपाल सिंह चौधरी के 15 मार्च, 2007 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 अप्रैल, 1931 को हुआ। वे 1987 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। 1990-1991 के दौरान वे राज्य मंत्री बने। वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक भूतपूर्व विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में जो शोक प्रस्ताव श्री जगपाल सिंह चौधरी, भूतपूर्व मंत्री के दुःखद निधन पर सदन के नेता द्वारा लाया गया है, मैं भी अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूँ। श्री जगपाल सिंह चौधरी 1990-91 के दौरान हरियाणा के राज्य मंत्री रहे। उन्होंने प्रदेश की अपने तकनीकी ज्ञान के साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इंजीनियर-इन-चीफ के रूप में तथा मंत्री के रूप में अभूतपूर्व सेवा की। प्रदेश के विकास में उनका योगदान सराहनीय था। वे हमारे साथ 1987 में विधायक भी रहे। उनका व्यवहार बहुत कुशल था और वे जनहित के मुद्दों को लेकर भी काफी संघर्षरत रहे थे। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शोक संतप्त परिवार तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जाएगी। अब मैं दिवंगत के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

वर्ष 2007-2008 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2007-2008.

Finance Minister (Sh. Birender Singh) : Hon'ble Mr. Speaker, as I rise to present the Budget Estimates for the year 2007-08, I do so with the confidence of making a positive impact on the destiny of our people and ushering in a new era of prosperity in the State.

2. Speaker, Sir, this is the third budget of our Government. While presenting the second Budget on 17th March, 2006 in this august House I had assured that Rs. 3300 crore proposed for the Annual Plan 2006-07 would be utilized optimally for the all round development of the State. I had also given a commitment that the emphasis would be on performance and quality. What does our report card say, one may legitimately ask ?

3. Sir, the actual development expenditure under Annual Plan 2006-07 is likely to be Rs. 4085 crore, which is Rs. 785 crore more than the approved outlay. Previous Governments used to regularly reduce the outlay for Plan expenditure, as they could neither mobilize the required resources nor curtail unnecessary expenditure. More fundamentally, they lacked a vision of the development needs of a modern Haryana and the aspirations of our people. Today, our fiscal management is reckoned as among the best in the country. It was highly appreciated by none other than the Deputy Chairman of the Planning Commission during the meeting held on 2nd March 2007 for finalization of the outlays for the Annual Plan 2007-08.

4. The Planning Commission was so impressed with our prudent fiscal management that it approved an outlay of Rs. 35,000 crore for the Eleventh Five Year Plan. It is a matter of immense pleasure and pride for every Haryanavi that this outlay is more than the combined total outlay of all the seven Five Year Plans implemented since the formation of Haryana in 1966. For the year 2007-08, which will be the first year of the Eleventh Plan, our outlay for development expenditure has been approved at Rs. 5,300 crore. Again, this is the highest ever Annual Plan in the history of Haryana.

5. Thanks to our diligent work in the first two years, we have amply demonstrated our ability to garner whatever financial resources that are needed in the pursuit of our vision of making Haryana the number one State in India. We are determined to ensure that Haryana remains in the forefront of the "India Growth Story" that the rest of the world is talking about. Be it the task of creation of world class infrastructure, introduction of the state-of-the-art technology, turning every inch of cultivable land into irrigated and double cropped area, provision of the best possible medical and educational facilities for all, we shall ensure that

adequate funds are allocated to all concerned agencies of the Government of Haryana. I intend to develop an institutional framework for engaging eminent professionals in various fields to help in formulating our long and medium term resource management and development planning. The task ahead is for Government organizations to gear themselves up to perform at much greater speed than they are used to. Having eliminated the perennial problems of shortages and delays in release of funds, the challenge before us now is to ensure execution of all projects in double quick time.

STATE ECONOMY

6. During 2005-06, the State Economy witnessed an excellent growth of 12.6 per cent in Gross State Domestic Product (GSDP) over the last year's level at current prices. When computed at constant prices, on the basis of 1999-2000 levels, this increase was 8.1 per cent. The growth in GSDP during 2006-07 is expected to be above 15 per cent at current prices and nearly 10.5 per cent at constant prices.

7. The Per Capita Income increased from Rs. 35,044 in 2004-05 to Rs. 38,832 in 2005-06 at current prices. At constant prices, it increased from Rs. 28,119 in the year 2004-05 to Rs. 29,887 in 2005-06. Haryana now has the second highest Per Capita Income among the States in India. This is indeed a highly creditable achievement. Yet, I assure you Sir, this is merely the beginning. We are aiming to substantially accelerate the growth rate in the coming years. My Budget proposals shall lay a solid foundation for our economy to take off.

8. The share of primary sector in GSDP during 2005-06 at constant prices (1999-2000 basis) is 23.3 per cent and the secondary and tertiary sectors contribute 32.4 percent and 44.3 per cent respectively. The trend of relative shares of these sectors is indicative of sound economic development. However, notwithstanding its relative share in the economy, we are ever conscious of the need to ensure at least four per cent growth in agriculture. I, assure you, Sir, that there shall be no dearth of funds for our earnest efforts to ensure that agriculture becomes an increasingly profitable profession. Farmers who feed the nation need to lead its march to prosperity.

Fiscal Management

9. Our Government is committed to derive maximum benefit out of the re-scheduling of loans and debt waiver offered by the Government of India as per recommendations of Twelfth Finance Commission. We are adhering to the fiscal correction path set for the Government in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005. Last year, I had informed the House that our revenue receipts are likely to increase by Rs. 600 crore over the Budget Estimates of 2005-06. I am happy to inform the House that the actual revenue receipts for 2005-06 were Rs. 1,816 crore more than the Budget Estimates. Similarly, in 2006-07 our revenue receipts are likely to be Rs. 2,171 crore than the Budget Estimates. This has been made possible by close monitoring by the Resource

Mobilization Committee chaired by the Chief Minister. I compliment all the employees of our revenue collecting agencies who rose to the occasion and improved the tax collection efficiency. We also need to place on record our thanks to the industrialists and traders of Haryana who by their better tax compliance have become active partners of the Government in the development process.

10. Without imposing any new burden on the tax payers, we had through improved tax collection efficiency and close monitoring of non-essential expenditure, achieved a revenue surplus of Rs. 1,213 crore in the year 2005-06. We would have repeated this feat in 2006-07 also. The previous Government had made a one-time settlement of Rs. 2,022 crore towards dues to Power Utilities in the year 2003-04. We had to adjust this amount in the State's accounts for the current year as revenue expenditure which was four years old expenditure but we have to show it in our budget. This has led to a revenue deficit of Rs. 653 crore, which otherwise would have been a surplus of Rs. 1369 crore. However, I expect to end the next year with a revenue surplus of Rs. 1,149 crore.

Significant New Initiatives

11. Speaker, Sir, now I would like to recapitulate a few significant new initiatives of our Government during 2006-07.

12. In the very first year of our Government we had removed the draconian law under which farmers could be arrested for default on dues to the Co-operatives. From 1st April 2006, the rate of interest on crop loan was reduced to seven per cent per annum as compared to eleven per cent in the previous years. More recently, we have announced a debt waiver scheme to benefit almost a million farmers and rural poor. Under this scheme, the entire interest liability of all those farmers, rural artisans and petty shopkeepers who were in default as on 31st March 2006, shall be waived if they repay their principal amount by 30th June 2007. Also an interest rebate of two per cent will be given to those farmers who repay their loans in time. The effective rate of interest charged will be five per cent only for such borrowers.

13. We have taken concrete steps to ensure additional generation of power within Haryana. Order has been placed during January 2007 for the construction of a coal-based thermal power plant of 1200 MW capacity at Hisar. This project is scheduled for commissioning by March 2010. Further, Aravalli Power Company, a joint venture between the Governments of Haryana, Delhi and the National Thermal Power Corporation has been incorporated for setting up a thermal power project of 1500 MW at Jhajjar. Haryana and Delhi will get 750 MW each from this project, which is scheduled for commissioning during 2010-11. Our policy to encourage renewable sources of energy has paid dividends. We have succeeded in signing Memoranda of Understanding with ten firms for setting up independent renewable energy projects with a total generation capacity of nearly 700 MW.

14. We have successfully concluded an agreement with Government of India and Delhi Metro Rail Corporation for extension of the Delhi Metro to

Gurgaon. Now we are making efforts to get similar links to other NCR towns of Haryana like Bahadurgarh and Faridabad. We have also paid the State Government's share towards the construction of Rohtak-Jhajjar-Rewari rail link during the year. The cost of this project is being shared equally between the Indian Railways and Haryana Government.

15. A new scheme has been launched by the name of "Indira Gandhi Drinking Water Supply Scheme" from November 2006, to provide water connections to all the scheduled caste households in the rural and urban areas, free of cost. This scheme is to be completed in a span of three years at an estimated cost of Rs. 340 crore. A concession of 50 per cent would also be extended to the scheduled caste households in the payment of monthly water tariff. Further, to encourage water connections to general category households, connection fee of Rs. 500 in the villages and Rs. 1,000 in the urban areas has been waived.

Brave Hearts of Haryana

16. Haryana is truly a Veer Bhumi. It is our duty to duly recognize and honour the contributions and sacrifices made by our brave soldiers and freedom fighters. We have substantially enhanced the amount of cash awards and the annuity being paid to gallantry award winners, both of the pre-independence and post-independence era irrespective of the ranks held by them in the defence forces. We are developing one more defence colony at Karnal. Excise duty has further been reduced on purchase of liquor by the defence and ex-defence personnel from CSD canteens. Monthly financial assistance being given to disabled ex-service men has been enhanced to Rs. 1,000 per month. The Samman Pension to freedom fighters, which we had earlier enhanced to Rs. 3,500 from Rs. 1,400 has been further increased to Rs. 5,125 per month.

Power

17. Considering the importance of electricity for the development of the State, we have given highest priority to the power sector. Despite the severe shortage of power in the northern grid during the year, eight per cent more power was supplied to the consumers this year till December 2006 compared to the corresponding period of last year.

18. We expect to bridge the gap between the demand and supply of power through a number of initiatives. The construction work of 600 MW Deen Bandhu Chhotu Ram Thermal Power Project, Yamunanagar is expected to be completed by February 2008. Power Purchase Agreements have also been signed for sourcing 770 MW Power from Independent Power Producers. Haryana has also consented to purchase about 1450 MW power on a long term basis from the four Ultra Mega Power Projects being set up in other parts of the country.

19. To strengthen the transmission and distribution system in the State, the State Power Utilities commissioned 36 new substations, augmented 124 existing substations and erected 834 kilometres of transmission lines with an

investment of about Rs. 300 crore since March 2005. In addition, over 19,719 distribution transformers have been added to the system to improve the quality of supply and more than 33, 892 tubewell connections have been released. Construction of 136 new substations and augmentation of 96 existing substations have been planned. Schemes worth Rs. 82 crore are being implemented under the 'Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana' for improving the rural electricity infrastructure and providing connections to rural poor households. To further improve power infrastructure, the State Government is committed to provide the required equity support of the Power Utilities to ensure investment of more than Rs. 20,000 crore during the Eleventh Plan period.

Irrigation

20. To fulfill the promise of ensuring equitable distribution of water, we have enhanced the availability of water to southern Haryana, which was neglected in the previous regime. Construction of the new canal linking Bhakra Main Line with Hansi Branch and Butana Branch has been taken up on a war-footing. This 109 kilometre long channel with a carrying capacity of 2000 cusecs would ensure equitable distribution of water in the State.

21. Similarly, work on the long awaited Shahbad-Dadupur-Nalvi canal has commenced for creating a head capacity of 590 cusecs. This canal and its distribution system, measuring 375 kilometres, will provide irrigation and recharge facilities to 92,532 hectares in Yamunanagar, Ambala and Kurukshetra districts. Work on the canal is in full swing.

22. Central Water Commission has cleared the construction of a dam on Kaushalya River at a cost of Rs. 51 crore and the work would be taken up during the year 2007. A project to increase the carrying capacity of Western Jamuna Canal Main Line lower from 14,000 cusecs to 20,000 cusecs at a cost of Rs. 30 crore is under implementation. The ground water recharge project at Masani Barrage in Rewari district has been taken up and shall be completed by June 2007. A project costing Rs. 454 crore for construction of watercourses in the Bhakra Canal and Western Jamuna Canal commands is being executed at a rapid pace as has been mentioned by the Chief Minister on 25th February, 2007 at Sirsa Rally and it would be completed within 2 years.

23. Sir, we are a water deficit State. But we are determined to take irrigation facilities to every cultivable field across the State so that every farmer is able to take crops in both the kharif and rabi seasons. But I will also call upon our hardworking peasantry to use this precious and scarce natural resource with utmost restraint. Farmers should give up the practice of flood irrigation and make use of the schemes launched by the Government for promotion of micro irrigation systems.

Drinking Water Supply and Sanitation

24. As on 1-4-2006, there were 1461 villages identified as having per capita supply of water less than the norm of 40 litres per capita per day. We have

taken up the work on augmentation of water supply in 725 of these deficient villages. Further, with the assistance from NABARD and NCR Planning Board, work for augmentation of water supply to 70 litre per capita per day has been taken up in 900 villages in 2006-07 and work in 1100 villages will be initiated in the coming year. Work on sewage treatment plants will be taken up in six towns of the State and the work of laying sewerage System is continuing in 35 towns.

25. The work for strengthening the existing water supply and sewerage infrastructure in NCR towns of Sonapat, Rohtak, Jhajjar, Rewari and Gurgaon as well as the counter magnet town of Hisar, implemented with loan assistance of the NCR Planning Board, is likely to be completed in 2007. Government of India has approved Rs. 62.50 crore under Yamuna Action Plan Phase-II, for preparation of Detailed Project Reports, public participation as well as institutional capacity building of Urban Local Bodies for eight towns viz Yamunanagar-Jagadhri, Karnal, Panipat, Sonipat, Faridabad, Gurgaon, Rohtak and Bahadurgarh.

Roads and Bridges

26. Roads and bridges are key infrastructure for socio-economic development of the State. We have taken several steps to strengthen and expand the road network. The State Government has got approved a number of National Highway Projects. These include the four laning of NH 22 from Zirakpur to Parwanoo, NH 71A from Panipat to Rohtak, NH 71 from Rohtak to Bawal and NH 10 from Delhi to Hisar. The National Highway Authority will also be taking up the six laning of NH 1, NH 2 and NH 8 in Haryana.

27. With the growth of rural economy, more and more demands are being received from the public for widening of existing roads and for construction of new roads. We have earmarked a sum of Rs.50 crore for the construction of new roads and Rs. 202.14 crore for repairs and maintenance of State roads. I am happy to state that we have increased the Plan allocation for roads and bridges from Rs. 225 crore in the year 2006-07 to Rs. 409 crore during the year 2007-08.

Agriculture and allied activities

28. Our Government has made efforts to tackle the problem of declining farm productivity. Now, there are definite indications of renewal and rejuvenation in the agriculture sector. Despite 40 per cent deficiency in rainfall, an all-time high production of 45 lakh tonnes of foodgrains was achieved during kharif 2006. This amounted to 11.4 per cent growth over the foodgrain production of 39.87 lakh tonnes during kharif 2005-06. This achievement is all the more significant in the light of the fact that there was a conscious State sponsored campaign to wean away the farmers from cultivation of water guzzling summer paddy known as saathi. The productivity of rice, bajra and cotton has also increased appreciably. Similarly, we have taken up a campaign to raise the productivity in wheat, which has stagnated over the years, by motivating the farmers to take up early sowing and to treat the seeds before sowing.

11.00 बजे 29. We also want our farmers to get the most remunerative prices for their produce. Our Government has raised the State Advisory Price of sugarcane by Rs. 21 per quintal in the last two years. We have also launched a campaign in February 2007 to double the productivity of sugarcane in the next two years. Buoyed by the success of our experiments in enabling our farmers to get better prices through direct marketing, contract farming and future markets, we have begun up-scaling these activities through Haryana State Agricultural Marketing Board, HAFED and Directorate of Agriculture. Last year, our Government had brought mustard and gram crops under the cover of National Agriculture Insurance Scheme for the first time. The benefit of this decision to the farmers of the State is evident from the fact that while the total premium paid by the farmers for these two crops was only Rs. 1.90 crore, a sum Rs. 15.28 crore was given as compensation to 24,692 farmers for losses incurred due to frost.

30. The Union Finance Minister has state in his Budget Speech of 2007-08 that we must find an alternative to the current way of administering the fertilizer subsidy and see that the farmers are given direct benefit. I welcome his statement. We should not restrict ourselves to the fertilizer subsidy alone. We must identify all the indirect subsidies to the agriculture sector and devise methods to provide all such subsidies directly to the farmers. If the principle of a reasonable profit margin over the actual cost of cultivation is accepted and the market for farm produce is assured, we will be in a position to reduce the indirect subsidies on various inputs by giving a higher procurement or support price.

31. After the first green revolution, we have not had any further significant break-through for increasing farm productivity. I call upon our talented pool of agricultural scientists to rise to the occasion and work for another quantum jump in agricultural production. The need of the hour, as the eminent agricultural scientist Dr. M.S. Swaminathan has put it, is to ensure a 'evergreen revolution'. This would involve continued improvements in productivity, economy in the use of water and optimisation of soil health. We also need to provide complete information on the national as well as international market prices and trends for agricultural commodities to our farmers to help them plan their production.

32. We are laying emphasis on improvement of genetic stock of our livestock with special attention towards preservation, multiplication and improvement of indigenous species such as Murrah breed of buffaloes and Haryana and Sahiwal breeds of cows. To provide quality veterinary services, selected district hospitals are being upgraded in a phased manner. Opening/upgrading of 60 veterinary institutions is also being taken up.

Rural Development

33. Providing civic amenities in all our villages at par with the urban areas is a commitment that we made in our party manifesto. To accelerate the implementation of this promise, our Government has decided to establish a Haryana Rural Development Authority on the pattern of Haryana Urban Development

Authority. This Authority would take up the planning and development of improved residential facilities and civic infrastructure in villages and semi urban areas.

34. The Government has released special grant of Rs. 75 crore for developing 59 villages as model villages during 2006-07. I propose to increase this ad hoc grant to Rs. 100 crore during 2007-08. We have provided Rs. ten lakh each to 1300 villages during the current year for cement concrete pavement of streets. Under the total sanitation campaign more than four lakh individual toilets, nearly six thousand schools/anganwari toilets and 392 women sanitary complexes have been constructed in the past two years. The HRDF Board has allocated Rs. 170 crore in the current financial year for undertaking various rural development works in the villages. This amount is over and above the budgetary allocation.

35. Our Government is conscious of the fact that Panchayati Raj Institutions can play a pivotal role in rural development. We have allowed payment of honorarium of Rs. 1,000 per month for Sarpanches and Rs. 200 per month for Panches. In order to improve transparency, accountability and quality in rural development works, the Gram Panchayats have been empowered to execute works up to Rs. three lakh themselves and works above Rs. three lakh shall be executed through contractors appointed by resorting to proper tendering process.

Urban Development

36. To meet the infrastructural and civic services requirements of the urban areas in the State, our Government is committed to make higher budgetary allocation to the Urban Local Bodies. During 2006-07, Rs. 198 crore was released for development works to municipalities on account of LADT collections, grants recommended by 12th Finance Commission and other ad hoc grants.

37. The State Government has signed a memorandum of agreement with Government of India under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. During 2007-08, major infrastructure development works will be taken up in the mission identified town of Faridabad, under this programme. City Development Plans have been prepared for all the major towns in Haryana by commissioning consultants. These plans will help to channelise and optimize our development effort and expenditure in these towns.

38. Our Government has also created a 'Fund for development of major infrastructure' in the State to be utilized for projects related to development of National/State Highways, mass rapid transport projects like Metro, water supply, power etc. The infrastructure development charges levied on private as well as public sector colonizers, Special Economic Zones and other land based development projects will form the corpus and continued source for the Fund.

39. HUDA has been asked to implement a scheme called 'Ashiana' for constructing four storey flats in various urban estates to be allotted to persons

belonging to economically weaker sections of society. HUDA has also decided to give 90 per cent rebate on payment of extension fee on properties exclusively owned by women. This rebate shall be 100 per cent for properties owned by widows.

Education and Sports

40. Our Government attaches the highest priority to improve the educational facilities as well as the quality of education imparted in the State. In today's competitive world, we wish to equip our youth with such skills and knowledge that would help them benefit from the expanding employment opportunities not only in India but abroad as well. Quality education is the polish that will make our youth sparkle like diamonds. For expanding higher education for women, a Women University has been established. This Private Universities Act passed by the State Legislature will open new avenues for expansion of higher education in the State. The Rajiv Gandhi Education City proposed at Kundli is likely to attract the best names in the field of higher education both at national and international level to establish world-class educational institutions in the State.

41. The scheme of semesterisation introduced last year has yielded good results in terms of regularity of studies, as well as for empowering teachers and reducing the 'stress' on children. For improving the quality of education, as proposed last year, action has been initiated to set up one model school in every district. It is proposed to provide free computer education in the coming year to all students from class six to twelve. Expansion of EDUSAT coverage to primary schools, Arts senior secondary schools and technical institutions will be taken up in the next year to impart quality education.

42. Hon'ble Members may be aware that the Union Finance Minister in his budget speech for 2007-08 has announced a massive hike in the allocations to education sector. However the pattern of assistance for Sarv Shiksha Abhiyan has been changed from the existing ratio of 75:25 between Centre and State to 50:50. Consequently, we have enhanced the allocation under SSA for the coming year. The plan allocation of Education Department has been raised by 90 per cent from Rs. 290 crore in 2006-07 to Rs. 540 crore for 2007-08.

43. The State Government has adopted a focused approach towards improving sports infrastructure. It has been proposed to set up a modern sports complex at Rohtak. An indoor hall is being constructed at Motilal Nehru School of Sports, Rai at a cost of Rs. 2.40 crore. We propose to construct one rural stadium costing Rs. 40 lakh each in every block. It is also proposed to set up a Sports Academy with all modern facilities in the State.

Health Services

44. Improvement of the health infrastructure and health infrastructure and services delivery in the State is given very high priority by our Government.

We have added three Community Health Centres, three Primary Health Centres and emergency services in three more hospitals. We have also added 399 delivery huts in the rural areas to support institutional deliveries for women. A project titled Reproductive Child Health-II under National Rural Health Mission, with a total outlay of Rs. 749 crore, has been launched in the State for improving the availability and access to quality health services.

45. Our efforts made during the last two years have yielded encouraging results. A recent survey conducted by Government of India shows that Maternal Mortality Rate and Infant Mortality Rate in the State are showing a declining trend. Institutional deliveries have gone up from 23 percent in 2004 to 46 percent by the end of 2006. We have extended the 'VIKALP' scheme started as a pilot project in four districts during 2005-06 to all the districts in the State during 2006-07. Memoranda of Understanding have been signed with 96 private health providers for providing health facilities to people living below the poverty line.

Welfare of Weaker Sections

46. The core theme of the Eleventh Five Year Plan as mentioned in the approach paper and approved by the National Development Council is inclusive growth. We have taken many new initiatives to ensure that the weaker sections of the society particularly those belonging to scheduled castes and backward classes are given a significant share in the development process.

We have increased the scholarship rates given to the scheduled caste students from Rs. 30 to Rs. 75 per month for students in the 6th to 8th classes and from Rs. 40 to Rs. 100 per month for students in the 9th to 12th classes. The grant for the purchase of stationery articles given to the scheduled caste students has also been enhanced from Rs. 80 to Rs. 150 per annum for 6th to 8th classes and Rs. 120 to Rs. 200 per annum for 9th to 12th classes.

47. The financial assistance for providing coaching to SC and BC candidates for the competitive examinations held by the Union Public Service Commission has been enhanced from Rs. 4,000 to Rs. 10,000 and for all other competitive/entrance examinations, the assistance has been increased to Rs. 8,000 as compared to the previous level of Rs. 3,000. The income ceiling under this scheme has also been raised from Rs. 44,500 to Rs. one lakh per annum. Similarly, the amount of subsidy given for construction of houses to scheduled castes and denotified tribes has been enhanced from Rs. 10,000 to Rs. 50,000.

48. Under "Indira Gandhi Priyadarshani Vivah Shagun Yojana" for the marriage of daughters of persons living below poverty line, a grant of Rs. 15,000 is being provided for scheduled caste families and Rs. 5,100 for other sections of society. For all widows living below the poverty line, irrespective of their caste, the financial assistance under the scheme is Rs. 15,000. With a view to encourage inter-caste marriages for social integration, we have increased the incentive amount from Rs. 25,000 to Rs. 50,000.

Women and Child Development

49. Women are the active promoters and facilitators of social transformation. Haryana has often been criticized for the bias against women in general and the girl child in particular. We are determined to change this perception and the situation within a definite time frame. As organization of women with common objectives would inevitably lead to empowerment, a new initiative for setting up committees of women in each village comprising of all women panches, educated adolescent girls, representatives of Mahila Mandals, Self Help Groups, war widows, social activists and key functionaries of the village has been launched. More than 6500 village committees have started functioning and are holding their monthly meetings. Another initiative in this direction is the constitution of 'Sakshar Mahila Samooh' to incorporate educated women and girls in every village to lend support to the Gram Panchayat. Such an organized pool of educated women and girls in the villages would become an important vehicle for generating awareness among women on key women related issues.

50. Eradication of malnutrition among children is one of the top priorities of our Government. In a major initiative, we have decided to procure supplementary nutrition through Self Help Groups with effect from 1-1-2007. This would lead to greater acceptance of the items for supplementary nutrition in the Integrated Child Development Services Programme. In addition, this would result in income generation for over 75,000 women in the State. We have increased the norms of nutrition from Rs. two to Rs. three per child beneficiary per day and from Rs. 2.50 to Rs. five in the case of pregnant women and nursing mothers. Haryana is the first State to provide such a high increase over the Central Government norms.

Industrial Training and Technical Education

51. The demand for skilled manpower is growing fast with the rapid growth of industry. To meet this demand the State is imparting industrial training and vocational education through 194 institutes, including 31 institutes for women. In order to establish institute-industry partnership, our Government has so far established Institute Managing Committees in 11 institutions and we propose to extend such collaboration to the remaining institutes in a phased manner. A new scheme titled "Skill training to scheduled caste students" is also proposed to be started exclusively for the scheduled caste students in new emerging areas like mobile phone and computer repair, networking, personal grooming, retailing etc.

52. There are 53 polytechnics, two technical universities, 44 engineering colleges and 19 pharmacy institutes operating in the State. There is a plan to add at least three more polytechnics during the Eleventh Five Year Plan. Introduction of new courses based on the emerging industry and technological trends in the engineering colleges will be given priority.

Industries

53. Haryana is heading towards new horizons of industrial growth. The New Industrial Policy of 2005 has played a prominent role in creating a global platform for industries in Haryana. The State has witnessed an unprecedented flow of investment to the tune of about Rs. 22,000 crore since the announcement of this Policy. Projects with an investment of more than Rs. 53,000 crore are also in the pipeline.

54. The State has received 72 proposals for the setting up of Special Economic Zones. Out of these 49 proposals have received approval, in principle, from Government of India. Four new projects for the setting up of industrial model townships have been initiated at Faridabad, Rohtak, Jagadhri and Kharkhoda. Three new Research and Development projects have been initiated in the State with assistance from Government of India. These are namely the Central Institute of Plastic & Engineering Technology at Panipat, the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management at Kundli and the National Automotive Testing and Research and Development Infrastructure Project at Manesar.

Labour and Employment

55. Haryana is known for its excellent track record of good industrial relations and industrial safety. We continue to provide a conducive environment through progressive policies and improved facilities for resolving industrial disputes. We have recently simplified the procedure for registration, licensing and approval of factory building plans under the Factories Act, 1948. Two more Labour Courts have been added to the existing seven such courts to expedite resolution of labour related disputes. New posts of Additional Labour Commissioner and Deputy Labour Commissioner have been created at Gurgaon for effective implementation of labour laws. Recently we have revised the minimum wages of unskilled workers to Rs. 3,510 per month, which is the highest in the country.

56. In the last budget speech, I had announced the establishment of Overseas Placement Bureau to facilitate employment of Haryana youth in foreign countries. This Bureau has started its operations and an Overseas Placement Committee has been constituted to strengthen its functioning. Any person can make use of its services free on the web also. Similarly, we have also started on-line services for facilitating placement in the private sector. Any applicant or employer can make use of these services free of charge. A Private Placement Cell has been established at Gurgaon for such facilities.

Welfare of Government Employees

57. I am happy to announce that we have fulfilled our promise of taking back the Group C and D employees retrenched by the previous Government. We have also initiated the process to absorb the retrenched Group A and B employees. We have restored the facility of Leave Travel Concession to State Government

employees, which has been a long pending demand. We are also committed to revise the pay scales of our employees on the pattern of the Central Government whenever the recommendations of the Sixth Central Pay Commission are implemented. We will also constitute a Commission to examine and settle within a definite time frame, all grievances relating to perceived anomalies that may arise on the revision of pay scales.

Tax Reforms

58. Tax structure has been rationalized in the overall interest of consumers, manufactures, traders and farmers. All goods sold to parents of deceased unmarried servicemen and widows of servicemen have been exempted from levy of VAT. Similarly, gur, shakkar, crudely tanned leather, hawan samgri, papad and small dhabas etc. have also been totally exempted from VAT. Rates of VAT have been reduced from 12.5 percent to four percent in case of pump sets below five horse power, honey, buttons, fly ash made bricks, katha, paper & plastic cups, paper pulp moulded trays, toys, desi ghee, candle, industrial tools and wood and timber etc.

59. These benefits by way of exemption/reduction to the public amounts to Rs. 135 crore per annum. Despite wide ranging relief granted to various segments of society, our VAT collection efforts have recorded an increase of 21 percent up to January, 2007 when compared to collections during the corresponding period of the last year.

60. The concept of Nega Watts-the saving of power through more efficient devices and other techniques-is gaining currency in developed countries. To encourage conservation of power in the State, I propose to give tax relief on Compact Fluorescent Lamps and other energy saving devices in consultation with the Empowered Committee of State Finance Ministers constituted by the Government of India.

61. The high incidence of passenger tax of 60 percent on the basic fare levied in Haryana has been drawing protests from all our neighboring States. This is an obstacle in getting more inter-state operations for Haryana Roadways. We have, therefore, decided to rationalize the passenger fare-passenger tax ratio. I propose to reduce the passenger tax to 25 percent and increase the basic fare proportionately without any change in the total fare payable by the passengers.

62. It is observed that a large number of banquet halls/lawns and marriage palaces have come up in the State. Events organized in these places lead to conspicuous consumption of electricity and place extra burden on all civic services. It is proposed to levy a cess on all such premises. The cess will be based in the total area of such premises and will be utilized towards development of civic amenities.

63. The Union Government has reduced the CST rate from four percent to three percent for the coming financial year. This is likely to entail a revenue loss

of Rs. 550 crore to the State exchequer. However the Government of India has assured that this revenue loss will be compensated through monetary and non-monetary measures.

Budget Estimates 2007-08

64. Hon'ble Speaker, I now present before this august House the budget estimates for the year 2007-08.

65. As I had mentioned in the beginning of my speech, allocation for the Annual Plan 2007-08 is proposed at Rs. 5,300 crore. Power sector would get Rs. 844 crore, Irrigation sector would get Rs. 718 crore, Water Supply and Sanitation would get Rs. 632 crore, Roads and Transport sector would get Rs. 505 crore. For other social sector programmes, the allocation would be Rs. 1,963 crore which would include Rs. 730 crore for Education including Industrial Training and Technical Education, Rs. 580 crore for Social Justice & Empowerment, Rs. 155 crore for Women and Child Development, Rs. 116 crore for Health Services and Rs. 100 crore for Welfare of SCs/BCs.

66. The year 2006-07 opened with a deficit of Rs. 236.61 crore as per RBI books and is likely to be closed with a deficit of Rs. 33.48 crore, with surplus transactions of Rs. 203.13 crore on year's account.

67. The financial year 2007-08 is likely to open with a deficit of Rs. 33.48 crore and to close with a deficit of Rs. 6.86 crore. The transactions on year's account, thus, show a surplus of Rs. 26.62 crore.

68. The Consolidated Fund of the State shows total receipts of Rs. 21,930.89 crore in Budget Estimates 2007-08 as against Rs. 20,074.31 crore in Revised Estimates 2006-07. The Budget proposals indicate an expenditure of Rs. 21,967.95 crore as against Rs. 19,801.72 crore in Revised Estimates of 2006-07. The Budget Estimates provide for State Plan outlay of Rs. 5,300 crore in addition to an outlay of Rs. 698.76 crore for Centrally Sponsored Schemes and other development plan schemes.

69. The revenue receipts in Budget Estimates 2007-08 are likely to increase by Rs. 1,999.24 crore to Rs. 17,917.35 crore from Rs. 15,918.11 crore in Revised Estimates of 2006-07. The revenue expenditure in Budget Estimates is estimated at Rs. 16,768.55 crore which is higher by Rs. 197.30 crore over the Revised Estimates of Rs. 16,571.25 crore in 2006-07. The Budget Estimates for 2007-08 show a revenue surplus of Rs. 1,148.80 crore.

70. The budget deficit is within manageable limits and the measures proposed for financial discipline are likely to help in eliminating the deficit. It is hoped that the share in central taxes and other devolutions would also go up as a result of higher expected growth in national economy. Similarly, the State tax revenue is also expected to increase substantially. I am confident that we will be

able to implement all our programmes successfully by full utilization of plan outlay with the cooperation and assistance of Hon'ble Members of this House and the people of Haryana.

71. Before I conclude, I acknowledge the untiring efforts of officers and employees of the Finance Department and the National Informatics Centre who worked hard to help me prepare the Budget proposals.

72. Sir, now commend the Budget Estimates 2007-08 for the consideration and approval of this august House.

JAI HIND !

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 19th March, 2007.

*11.36 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M., Tuesday, the 19th March, 2007)